Lakshya IAS
academy

14
Aug 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS

Mr. R.P. Singh Sir
(MD)

लक्ष्य IAS तेलीबाग लखनऊ
Lakshya IAS Academy
8182093320

1. केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी मिली

भारतीय संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को आधिकारिक रूप से पारित कर दिया है, जिससे 12 अगस्त को "केरल" राज्य का नाम बदलकर "केरलम" करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सबसे पहले लोकसभा ने इस कानून को पारित किया, जिसके बाद राज्यसभा ने भी इसे अपनी स्वीकृति दी। यह विधेयक संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि राज्य का नाम उसकी मूल भाषा मलयालम में दर्शाया जा सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रेखांकित किया कि यह कानून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव का सम्मान करता है, जिसमें केंद्र सरकार से संवैधानिक वर्तनी को मूल मलयालम उच्चारण के अनुरूप बनाने का अनुरोध किया गया था। इस प्रस्ताव को इससे पहले फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी।

मुख्य बिंदु:

- संवैधानिक संशोधन: यह विधेयक भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करता है ताकि राज्य का नाम "केरल" से बदलकर "केरलम" किया जा सके।
- विधायी समयसीमा: केरल विधानसभा ने मूल रूप से 2024 में नाम परिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने से पहले फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी।
- भाषाई सामंजस्य: नाम का यह परिवर्तन संविधान में राज्य के आधिकारिक नाम को मलयालम में इसके मूल उच्चारण और प्रयोग के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है।

1. Bill altering name of state of Kerala to Keralam gets nod from Parliament

The Parliament of India has officially passed the Kerala (Alteration of Name) Bill, 2026, paving the way to rename the state of "Kerala" to "Keralam" on 12th August. The Lok Sabha passed the legislation first, followed by the Rajya Sabha's approval. The bill seeks to amend the First Schedule of the Constitution to reflect the state's name in its native language, Malayalam. Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai highlighted that this legislation honors a 2024 resolution passed by the Kerala Legislative Assembly, which requested the central government to align the Constitutional spelling with the native Malayalam pronunciation. The proposal received approval from the Union Cabinet earlier in February 2026.

Key Points:

- Constitutional Amendment: The bill amends the First Schedule of the Constitution of India to change the state's name from "Kerala" to "Keralam".
- Legislative Timeline: The Kerala Legislative Assembly originally passed a resolution for the name change in 2024, which received Union Cabinet approval in February 2026 before being passed by both houses of Parliament.
- Linguistic Alignment: The name alteration seeks to align the official name of the state in the Constitution with its native pronunciation and usage in Malayalam.

2. बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाने के लिए ब्रिक्स देशों को मजबूत तंत्र की आवश्यकता

12 अगस्त को जयपुर में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के अवसर पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं से बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाने के लिए स्थिर और अनुमानित नीतिगत ढांचा स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हालांकि सार्वजनिक निवेश एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, लेकिन बहुपक्षीय विकास बैंक जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जोखिम को कम करने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और पीएम गति शक्ति जैसी भारत की रणनीतियों पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री ने रेखांकित किया कि कैसे सार्वजनिक पूंजीगत व्यय विकासशील देशों में सतत आर्थिक विकास और दीर्घकालिक निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है।

मुख्य बिंदु:

- स्थान और ध्यान केंद्रित विषय: निजी पूंजी जुटाने पर संगोष्ठी का आयोजन जयपुर में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान किया गया, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ भी उपस्थित थीं।
- बहुपक्षीय विकास बैंकों की भूमिका: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि बहुपक्षीय विकास बैंकों को निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे के निवेश के जोखिमों को कम करना होगा और परियोजनाओं की वित्तीय व्यावहारिकता में सुधार करना होगा।
- भारत का मॉडल: सार्वजनिक निवेश को निजी पूंजी के विकल्प के बजाय एक उत्प्रेरक के रूप में उजागर किया गया, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और पीएम गति शक्ति जैसे साधनों का लाभ उठाया गया।

2. BRICS nations need stronger frameworks to mobilise private capital at scale

Speaking at a seminar organized alongside the BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) meeting in Jaipur on 12th August, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman urged BRICS economies to establish stable, predictable policy frameworks to mobilize large-scale private capital. She emphasized that while public investment serves as a crucial catalyst, Multilateral Development Banks (MDBs), such as the New Development Bank (NDB), play a pivotal role in de-risking infrastructure projects and enhancing investor confidence. Highlighting India's strategies like Viability Gap Funding (VGF), Hybrid Annuity Models (HAM), Infrastructure Investment Trusts (InvITs), and PM Gati Shakti, the Finance Minister highlighted how public capital expenditure drives sustainable economic growth and long-term private sector participation across developing nations.

Key Points:

- Venue and Focus: The seminar on mobilising private capital was held on the sidelines of the BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) meeting in Jaipur, with New Development Bank (NDB) President Dilma Rousseff in attendance.
- Role of MDBs: Finance Minister Nirmala Sitharaman underscored that Multilateral Development Banks must de-risk infrastructure investments and improve project bankability to draw in private capital.
- India's Model: Public investment was highlighted as a catalyst rather than a replacement for private capital, leveraging tools like Viability Gap Funding (VGF), Infrastructure Investment Trusts (InvITs), and PM Gati Shakti.

3. अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत 'श्रुति'

11 अगस्त, 2026 को भारतीय नौसेना ने कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित अपना पहला अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत 'श्रुति' (यार्ड 3037) लॉन्च किया। स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत प्रोजेक्ट संयुक्त रूप से गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत की प्राचीन वैदिक विरासत के नाम पर रखे गए इस पोत के प्रतीक चिन्ह पर लाल और सफेद रंग के लाइटहाउस के साथ उर्सा मेजर तारामंडल दर्शाया गया है। बहु-क्षेत्रीय अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया 'श्रुति' भारत की महत्वपूर्ण अपतटीय संपत्तियों और समुद्री हितों की रक्षा के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी, समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव, समुद्री डकैती विरोधी अभियानों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत का कार्य करेगा।

मुख्य बिंदु:

- निर्माता और स्थान: 'श्रुति' को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक संयुक्त अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में लॉन्च किया गया था।
- स्वदेशी क्षमताएं: यह पोत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो घरेलू युद्धपोत डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देता है।
- परिचालन क्षेत्र: इसे बहु-क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें खोज और बचाव, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी, समुद्री डकैती विरोधी अभियान और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत शामिल हैं।

3. Next-Generation Offshore Patrol Vessel 'Shruti'

On August 11, 2026, the Indian Navy launched 'Shruti' (Yard 3037), its first Next-Generation Offshore Patrol Vessel (NGOPV), built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) in Kolkata. The NGOPV project is being executed jointly by GRSE, Kolkata, and Goa Shipyard Limited (GSL), Goa, under the government's Aatmanirbhar Bharat initiative to enhance indigenous warship-building capabilities. Named after India's ancient Vedic heritage, the vessel features a crest displaying the Ursa Major constellation alongside a red-and-white lighthouse. Designed for multi-domain missions, 'Shruti' will perform EEZ surveillance, maritime security, search and rescue, anti-piracy operations, and Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) to safeguard India's critical offshore assets and maritime interests.

Key Points:

- Manufacturer and Location: 'Shruti' was launched at Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) in Kolkata as part of a joint NGOPV programme with Goa Shipyard Limited (GSL).
- Indigenous Capabilities: The vessel aligns with Aatmanirbhar Bharat and Make in India objectives, bolstering domestic warship design and construction.
- Operational Scope: Designed for multi-domain maritime security, including search and rescue, EEZ surveillance, anti-piracy operations, and Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

4. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 12 अगस्त को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा "ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स" का विमोचन किया। इस पुस्तक को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान बताते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यद्यपि संघर्ष व्यक्तिगत रूप से कोविंद का था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप मिली विजय भारतीय गणराज्य की है। प्रधानमंत्री ने कोविंद की प्रेरणादायक जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला, जो कानपुर देहात में बचपन की कठिनाइयों से उबरने से लेकर सांसद, राज्यपाल और अंततः भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा देने तक की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर और गांधी जैसे नेताओं के सामाजिक समानता के विचारों के साथ कोविंद के जुड़ाव के साथ-साथ 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व करने सहित उनके निरंतर राष्ट्रीय योगदान की सराहना की।

मुख्य बिंदु:

- आत्मकथा का विमोचन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा "ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माय लाइफ, माय स्ट्रगल्स" का आधिकारिक रूप से विमोचन किया।
- प्रेरणादायक यात्रा: यह पुस्तक कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) में साधारण पृष्ठभूमि से उठकर सर्वोच्च संवैधानिक और विधायी पदों को संभालने तक के कोविंद के सफर का वर्णन करती है।
- राष्ट्रीय भूमिकाएं: अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के अलावा, भारत के निरंतर लोकतांत्रिक सुधार एजेंडे में योगदान देने के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' समिति के कोविंद के नेतृत्व की भी सराहना की गई।

4. Autobiography of Former President Ram Nath Kovind Released

Prime Minister Narendra Modi on Wednesday 12 August released the autobiography of former Indian President Ram Nath Kovind, titled "Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles", at Vigyan Bhavan in New Delhi. Describing the book as a significant contribution to Indian democracy, PM Modi noted that while the struggles belonged personally to Kovind, the resulting triumph belonged to the Republic of India. The Prime Minister highlighted Kovind's inspiring trajectory, from overcoming childhood hardships in Kanpur Dehat to serving as Parliamentarian, Governor, and ultimately India's 14th President. PM Modi praised Kovind's alignment with the social equality visions of leaders like Ambedkar and Gandhi, as well as his ongoing national contributions, including leading the High-Level Committee on 'One Nation, One Election'.

Key Points:

- Autobiography Release: Prime Minister Narendra Modi officially launched former President Ram Nath Kovind's autobiography, "Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles", in New Delhi.
- Inspirational Journey: The book chronicles Kovind's rise from modest origins in Kanpur Dehat (Uttar Pradesh) to holding top constitutional and legislative offices.
- National Roles: Beyond his presidential tenure, Kovind's leadership of the 'One Nation, One Election' committee was lauded for contributing to India's ongoing democratic reform agenda.

5. खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता निलंबित की

12 अगस्त, 2026 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गंभीर प्रशासनिक खामियों के कारण टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता निलंबित कर दी। यह प्रशासनिक कार्रवाई तब की गई जब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने संगठनात्मक चुनाव कराने में विफल रहा और सरकार के कारण बताओ नोटिस का असंतोषजनक उत्तर दिया। खेल के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने और एथलीटों के हितों की रक्षा के लिए, मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ को भारत में टेबल टेनिस संचालन की देखरेख के लिए एक तदर्थ समिति स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, भारतीय ओलंपिक संघ अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ से परामर्श करेगा ताकि तब तक एक अंतरिम नियामक तंत्र लागू किया जा सके जब तक कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के अनुरूप एक अनुपालन शासन संरचना को बहाल नहीं कर लेता।

मुख्य बिंदु:

- निलंबन का कारण: टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रशासनिक विफलताओं, विशेष रूप से समय पर संगठनात्मक चुनाव कराने में असमर्थता और कारण बताओ नोटिस के असंतोषजनक उत्तर के कारण अपनी आधिकारिक मान्यता खो दी।
- अंतरिम प्रशासन: भारतीय ओलंपिक संघ को देश में टेबल टेनिस के दैनिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक तदर्थ समिति बनाने का काम सौंपा गया है।
- वैश्विक समन्वय: भारतीय ओलंपिक संघ अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के साथ मिलकर काम करेगा ताकि तब तक अंतर्राष्ट्रीय नियामक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके जब तक कि एक स्थायी, संहिता-अनुपालन महासंघ बहाल नहीं हो जाता।

5. Sports Ministry Suspends Table Tennis Federation of India Recognition

On August 12, 2026, the Ministry of Youth Affairs and Sports suspended the recognition of the Table Tennis Federation of India (TTFI) over severe governance deficiencies. The administrative action was taken after the TTFI failed to hold its organizational elections within the mandated timeframe and provided an unsatisfactory response to a government show-cause notice. To ensure the sport's continued functioning and protect athletes' interests, the Ministry directed the Indian Olympic Association (IOA) to establish an ad-hoc committee to oversee table tennis operations in India. Furthermore, the IOA will consult the International Table Tennis Federation (ITTF) to implement an interim regulatory mechanism until the TTFI restores a compliant governance structure aligned with the National Sports Development Code of India, 2011.

Key Points:

- Reason for Suspension: The TTFI lost its official recognition due to governance failures, specifically its inability to conduct timely organizational elections and a poor response to a show-cause notice.
- Interim Administration: The Indian Olympic Association (IOA) has been tasked with forming an ad-hoc committee to manage the day-to-day affairs of table tennis in the country.
- Global Coordination: The IOA will work with the International Table Tennis Federation (ITTF) to ensure international regulatory compliance until a permanent, Code-compliant federation is restored.

6. उत्तर-पूर्व भारत में कैस्केड मेंढक की तीन नई प्रजातियों की खोज

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस. डी. बीजू के नेतृत्व में एक टीम ने उत्तर-पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल में कैस्केड मेंढक की तीन नई प्रजातियों की खोज की है, जो 12 अगस्त को 'बुलेटिन ऑफ द म्यूजियम ऑफ कॉम्पेरेटिव जूलॉजी' में प्रकाशित हुआ। धाराओं में रहने वाले ये उभयचर 'अमोलोप्स' वंश से संबंधित हैं, जो पूर्वी हिमालय की तेज़ बहने वाली पहाड़ी धाराओं के अनुकूलित हैं। इन नई प्रजातियों में 'अमोलोप्स अम्माची' (त्रिपुरा की जंपुई पहाड़ियों में पाया गया), 'अमोलोप्स सेंडेन्यू' (नागालैंड में दर्ज) और 'अमोलोप्स बेला' (विशिष्ट हरे और लाल-भूरे रंग के पैटर्न के साथ पश्चिम बंगाल में खोजा गया) शामिल हैं। 300 आबादी के डीएनए विश्लेषण और आकृति विज्ञान अध्ययनों का उपयोग करते हुए, शोध ने पहली बार भारत में पांच अतिरिक्त अमोलोप्स प्रजातियों को भी दर्ज किया, जिससे इस क्षेत्र की ज्ञात जैव विविधता का विस्तार हुआ।

मुख्य बिंदु:

- खोज और वंश: त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में तेज़ बहने वाली पहाड़ी धाराओं के अनुकूलित 'अमोलोप्स' वंश से संबंधित कैस्केड मेंढक की तीन नई प्रजातियों की खोज की गई।
- प्रजातियों के नाम और स्थान: नई पहचानी गई प्रजातियां 'अमोलोप्स अम्माची' (त्रिपुरा), 'अमोलोप्स सेंडेन्यू' (नागालैंड) और 'अमोलोप्स बेला' (पश्चिम बंगाल) हैं।
- शोध नेतृत्व: यह अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस. डी. बीजू (जिन्हें "फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया" के रूप में जाना जाता है) के नेतृत्व में किया गया था और इसने पहली बार भारत में पांच अन्य अमोलोप्स प्रजातियों को भी दर्ज किया।

6. Three new cascade frog species discovered in northeast India

A team led by Delhi University's Prof. S. D. Biju discovered three new cascade frog species across Northeast India and West Bengal, published in the Bulletin of the Museum of Comparative Zoology on 12 August. These stream-dwelling amphibians belong to the genus Amolops, adapted to fast-flowing hill torrents in the Eastern Himalayas. The new species include Amolops ammachi (found in Tripura's Jampui Hills), Amolops sendenyu (recorded in Nagaland), and Amolops bella (discovered in West Bengal with distinct green and reddish-brown patterns). Utilizing DNA analysis and morphological studies across 300 populations, the research also documented five additional Amolops species in India for the first time, expanding the known biodiversity of the region.

Key Points:

- Discovery and Genus: Three new cascade frog species belonging to the genus Amolops—adapted to fast-flowing hill streams—were discovered across Tripura, Nagaland, and West Bengal.
- Species Names and Locations: The newly identified species are Amolops ammachi (Tripura), Amolops sendenyu (Nagaland), and Amolops bella (West Bengal).
- Research Leadership: The study was led by DU professor S. D. Biju (known as the "Frogman of India") and also recorded five other Amolops species in India for the first time.

7. 'एक जड़ी-बूटी, एक मानक' पहल को तीन साल का विस्तार मिला

आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार 12 अगस्त को 'एक जड़ी-बूटी, एक मानक' पहल के तहत अपनी साझेदारी को तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग तथा भारतीय फार्माकोपिया आयोग के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया। 2022 से इसके पहले चरण के दौरान विकसित 50 मोनोग्राफ के आधार पर, इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों के लिए समान और वैज्ञानिक रूप से विश्वसनीय मानक स्थापित करना है। भारतीय वनस्पति मानकों को वैश्विक गुणवत्ता मानदंडों के साथ संरेखित करके, इस ढांचे का लक्ष्य अस्पष्टता को कम करना, गुणवत्ता आश्वासन में सुधार करना, निर्यात को बढ़ावा देना और व्यापार करने में सुगमता प्रदान करना है।

मुख्य बिंदु:

- समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण: भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग तथा भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने 'एक जड़ी-बूटी, एक मानक' पहल के तहत औषधीय पौधों के लिए एकीकृत वैज्ञानिक मानक स्थापित करने हेतु तीन साल के लिए अपने समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया।
- प्रणालियों में दायरा: यह ढांचा आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी में उपयोग की जाने वाली व्यक्तिगत जड़ी-बूटियों के लिए एक एकल, सामंजस्यपूर्ण मानक बनाता है।
- वैश्विक गुणवत्ता संरेखण: प्रारंभिक 50 मोनोग्राफ के आधार पर निर्मित यह पहल भारतीय पारंपरिक दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू गुणवत्ता मानदंडों को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ती है।

7. 'One Herb, One Standard' initiative gets three-year extension

The Ministry of Ayush and the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) have extended their partnership under the "One Herb, One Standard" initiative for three years on Wednesday 12 August. The Memorandum of Understanding (MoU) was renewed between the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine and Homoeopathy (PCIM and H) and the Indian Pharmacopoeia Commission (IPC). Building on the 50 monographs developed during its first phase since 2022, this initiative seeks to establish uniform, scientifically reliable standards for medicinal plants used across traditional systems like Ayurveda, Siddha, Sowa-Rigpa, Unani, and Homoeopathy. By aligning Indian botanical standards with global quality benchmarks, the framework aims to reduce ambiguity, improve quality assurance, boost exports, and facilitate ease of doing business.

Key Points:

- MoU Renewal: PCIMandH and IPC renewed their MoU for three years to establish unified scientific standards for medicinal plants under the "One Herb, One Standard" initiative.
- Scope Across Systems: The framework creates a single, harmonized standard for individual herbs used across Ayurveda, Siddha, Sowa-Rigpa, Unani, and Homoeopathy.
- Global Quality Alignment: Building on 50 initial monographs, the initiative aligns domestic quality benchmarks with global standards to boost the international credibility and export potential of Indian traditional medicines.

8. हरियाली अमावस्या पर 31 राज्यों में 50,000 पौधे लगाए गए

12 अगस्त को हरियाली अमावस्या के अवसर पर केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चलाए गए एक राष्ट्रव्यापी हरित अभियान के तहत 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। वृक्ष मित्र परिवार के सहयोग से आयोजित इस अभियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को और मजबूती दी। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम के पास पीबीजी ग्राउंड में आयोजित हुआ, जिसके साथ ही पूरे भारत के गांवों, पंचायतों और कस्बों में स्थानीय स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाए गए। मंत्री चौहान ने रेखांकित किया कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति भारत की पारंपरिक कृतज्ञता को दर्शाती है। उन्होंने नागरिकों से पौधों के संरक्षण और दीर्घकालिक देखभाल को भावी पीढ़ियों के लिए एक आवश्यक निवेश के रूप में अपनाने का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रव्यापी स्तर: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वृक्ष मित्र परिवार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस अभियान के तहत एक ही दिन में 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए।
- अवसर और तालमेल: प्रधानमंत्री मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरणा लेते हुए पारंपरिक प्रकृति संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए यह अभियान हरियाली अमावस्या पर आयोजित किया गया था।
- पौधों की देखभाल पर ध्यान: इसमें पौधों के दीर्घकालिक संरक्षण पर जोर दिया गया और नागरिकों को वृक्षारोपण तथा बाद में देखभाल के माध्यम से जीवन के प्रमुख पड़ावों को 'वृक्ष पर्व' के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया गया।

8. 50,000 saplings planted across 31 states on Hariyali Amavasya

On the occasion of Hariyali Amavasya, on 12 August, a nationwide green initiative led by Union Agriculture, Farmers' Welfare, and Rural Development Minister Shivraj Singh Chouhan saw over 50,000 saplings planted across 31 states. Organized in collaboration with the Vriksh Mitra Parivar, the campaign complemented Prime Minister Narendra Modi's 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign. The central event took place at the PBG Ground near Talkatora Stadium in New Delhi, alongside localized drives in villages, panchayats, and towns across India. Minister Chouhan highlighted that Hariyali Amavasya reflects India's traditional gratitude toward nature, urging citizens to treat sapling survival and long-term nurturing as an essential investment in future generations.

Key Points:

- Nationwide Scale: Over 50,000 saplings were planted across 31 states in a single day, organized jointly by Union Minister Shivraj Singh Chouhan and the Vriksh Mitra Parivar.
- Occasion and Synergy: The drive was celebrated on Hariyali Amavasya to reinforce traditional nature conservation while drawing momentum from PM Modi's 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign.
- Focus on Nurturing: Emphasized long-term survival, encouraging citizens to celebrate major life milestones as 'Vriksh Parv' through tree planting and post-plantation care.

9. रूस ने पहली बार भारत से पेट्रोल खरीदा

- अगस्त 2026 में, रूस ने अपने तेल शोधनागारों (रिफाइनरियों) पर हुए ड्रोन हमलों के कारण उत्पन्न घरेलू ईंधन की कमी से निपटने के लिए इतिहास में पहली बार भारत से पेट्रोल (गैसोलीन) का आयात शुरू किया। पहली खेप में 42,000 टन पेट्रोल शामिल था, जिसे गुजरात में रोज़नेफ़्ट समर्थित नायरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा संचालित वाडीनार रिफाइनरी से लोड किया गया था और मिस्र के दामिएटा बंदरगाह के रास्ते रूस भेजा गया था। आपूर्ति के इस संकट के कारण रूसी कच्चे तेल की प्रसंस्करण दरों में मौसमी स्तर की तुलना में लगभग एक-तिहाई की गिरावट आई, जिससे मास्को को घरेलू ईंधन निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और भारत तथा बेलारूस जैसे देशों से आयात पर निर्भर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह व्यापार भारत द्वारा कच्चे तेल के एक प्रमुख प्रसंस्करक (प्रोसेसर) के रूप में अपनी भूमिका के विस्तार के बल पर, वैश्विक ऊर्जा गतिशीलता में आ रहे बदलावों को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु:

- ऐतिहासिक पहली बार: रूस ने अपने तेल शोधनागारों पर हुए लक्षित हमलों के परिणामस्वरूप उत्पन्न घरेलू कमी को पूरा करने के लिए इतिहास में पहली बार भारत से पेट्रोल का आयात किया।
- रिफाइनरी और रसद (लॉजिस्टिक्स): शुरुआती 42,000 टन की खेप गुजरात की वाडीनार रिफाइनरी (नायरा एनर्जी द्वारा संचालित) से भेजी गई थी और मिस्र के दामिएटा बंदरगाह के माध्यम से ट्रांसशिप की गई थी।
- घरेलू संकट: कम रिफाइनिंग उत्पादन - जो मौसमी औसत से लगभग एक-तिहाई नीचे गिर गया - ने रूस को अपने ईंधन निर्यात को रोकने और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सहयोगी देशों की ओर रुख करने के लिए मजबूर किया।

9. Russia Buys Gasoline From India For First Time

- In August 2026, Russia began importing gasoline from India for the first time in history to address domestic fuel shortages caused by drone strikes on its oil refineries. The initial shipment involved 42,000 tonnes of gasoline loaded from the Vadinar refinery in Gujarat, operated by Rosneft-backed Nayara Energy Ltd. and routed to Russia via the Egyptian port of Damietta. The supply crunch led Russian crude processing rates to drop nearly one-third below seasonal levels, prompting Moscow to enforce a ban on domestic fuel exports and rely on imports from countries like India and Belarus. This trade highlights evolving global energy dynamics, supported by India's expanding role as a major processor of crude oil.

Key Points:

- Historic First: Russia imported gasoline from India for the first time in history to offset domestic shortages resulting from targeted attacks on Russian oil refineries.
- Refinery and Logistics: The initial 42,000-tonne shipment originated from the Vadinar refinery in Gujarat (operated by Nayara Energy) and was transshipped through Damietta Port, Egypt.
- Domestic Crisis: Reduced refining output—falling nearly one-third below seasonal averages—forced Russia to halt its own fuel exports and turn to partner nations to fulfill domestic demand.

10. एम्जेन हैदराबाद में विज्ञान एवं नवोन्मेष केंद्र खोलेगा

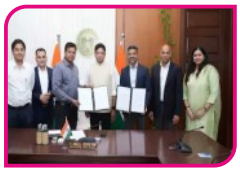

वैश्विक बायोटेक्नोलॉजी दिग्गज एम्जेन ने 12 अगस्त को तेलंगाना सरकार के साथ हैदराबाद के जीनोम वैली में एक नया विज्ञान एवं नवोन्मेष केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2027 में चालू होने के लिए नियोजित, यह सुविधा एम्जेन के वैश्विक अनुसंधान और विकास नेटवर्क में शामिल होगी और इससे लगभग 200 उच्च कुशल नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। यह केंद्र डिस्कवरी केमिस्ट्री, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्नत तकनीक के साथ प्रयोगशाला अनुसंधान को एकीकृत करके, एम्जेन का लक्ष्य वैश्विक जीवन विज्ञान केंद्र के रूप में हैदराबाद की स्थिति को मजबूत करते हुए, दवा की खोज में तेजी लाना है।

मुख्य बिंदु:

- स्थान और अवसंरचना: एम्जेन भारत के प्रमुख जीवन विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी क्लस्टर, हैदराबाद के जीनोम वैली में अपना नया विज्ञान एवं नवोन्मेष केंद्र स्थापित कर रहा है।
- ध्यान केंद्रित क्षेत्र: यह सुविधा डिस्कवरी केमिस्ट्री, प्रिसिजन मेडिसिन, डेटा साइंस तथा ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में विशेषज्ञता हासिल करेगी।
- वैश्विक अनुसंधान एवं विकास एकीकरण: 2027 में खुलने की उम्मीद, यह केंद्र लगभग 200 उच्च-कुशल नौकरियां पैदा करेगा और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के एम्जेन के मौजूदा वैश्विक नेटवर्क के साथ सीधे एकीकृत होगा।

★★★

10. Amgen to Open Science and Innovation Centre in Hyderabad

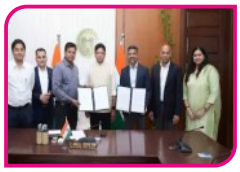

Global biotechnology major Amgen signed a Memorandum of Understanding (MoU), on August 12, with the Government of Telangana to set up a new Science and Innovation Centre at Genome Valley in Hyderabad. Planned to become operational in 2027, the facility will join Amgen's global Research and Development network and is expected to create around 200 highly skilled jobs. The centre will focus on discovery chemistry, drug metabolism and pharmacokinetics (DMPK), precision medicine, data science, and digital technologies. By integrating wet-laboratory research with advanced technology, Amgen aims to accelerate drug discovery, strengthening Hyderabad's position as a global life sciences hub.

Key Points:

- Location and Infrastructure: Amgen is establishing its new Science and Innovation Centre in Genome Valley, Hyderabad, India's prominent life sciences and biotechnology cluster.
- Focus Areas: The facility will specialize in discovery chemistry, precision medicine, data science, and drug metabolism and pharmacokinetics (DMPK).
- Global RandD Integration: Expected to open in 2027, the center will create about 200 high-skilled jobs and integrate directly with Amgen's existing global network of research laboratories.

★★★

दैनिक समसामयिक DAILY CURRENT AFFAIRS MCQs प्रश्नोत्तरी

Q1. वैश्विक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी एम्जेन ने तेलंगाना में नया विज्ञान एवं नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर में MoU पर हस्ताक्षर किया?

(a) वारंगल (b) हैदराबाद
(c) अमरावती (d) सिकंदराबाद

Q2. नायरा एनर्जी लिमिटेड द्वारा संचालित वाडीनार ऑयल रिफाइनरी, जहाँ से अगस्त 2026 में पहली बार रूस को पेट्रोल की आपूर्ति की गई, किस जिले में स्थित है?

(a) जामनगर (b) कच्छ
(c) देवभूमि द्वारका (d) राजकोट

Q3. 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

(a) शहरी व्यावसायिक वानिकी का विस्तार
(b) लकड़ी के निर्यात को बढ़ावा देना
(c) पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना
(d) तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव का पुनर्स्थापन

Q4. 'वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड' पहल को आगे बढ़ाने के लिए किन दो संस्थानों ने MoU का नवीनीकरण किया?

(a) FSSAI और CDSCO (b) ICMR और CSIR
(c) PCIM&H और IPC (d) NMPB और CCRAS

Q5. अगस्त 2026 में उत्तर-पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल में खोजी गई कैस्केड मेंढक की नई प्रजातियाँ किस वंश से संबंधित हैं?

(a) Rana (b) Amolops
(c) Fejervarya (d) Nyctibatrachus

Q1. In which city did the global biotechnology company Amgen sign an MoU with the Telangana government to establish a new Science and Innovation Center?

(a) Warangal (b) Hyderabad
(c) Amaravati (d) Secunderabad

Q2. The Vadinar Oil Refinery operated by Nayara Energy Limited, from where petrol was supplied to Russia for the first time in August 2026, is located in which district?

(a) Jamnagar
(b) Kutch
(c) Devbhumi Dwarka
(d) Rajkot

Q3. What is the primary objective of the 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign?

(a) Expansion of urban commercial forestry
(b) Promotion of timber exports
(c) Promotion of environmental conservation and tree plantation
(d) Restoration of mangroves in coastal areas

Q4. Which two institutions renewed the MoU to advance the 'One Herb, One Standard' initiative?

(a) FSSAI and CDSCO
(b) ICMR and CSIR
(c) PCIM&H and IPC
(d) NMPB and CCRAS

Q5. The new species of cascade frogs discovered in Northeast India and West Bengal in August 2026 belong to which genus?

(a) Rana (b) Amolops
(c) Fejervarya (d) Nyctibatrachus

Q6. टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) की मान्यता निलंबित होने के बाद खेल के संचालन के लिए तदर्थ समिति गठित करने का निर्देश किस संगठन को दिया गया?

(a) भारतीय खेल प्राधिकरण
(b) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
(c) अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ
(d) भारतीय ओलंपिक संघ

Q7. राम नाथ कोविंद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन-सा कार्यकाल पूरा किया था?

(a) 12वें राष्ट्रपति, 2007–2012
(b) 13वें राष्ट्रपति, 2012–2017
(c) 14वें राष्ट्रपति, 2017–2022
(d) 15वें राष्ट्रपति, 2022–वर्तमान

Q8. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

(a) मुंबई (b) कोच्चि
(c) कोलकाता (d) विशाखापत्तनम

Q9. 12 अगस्त 2026 को BRICS वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई?

(a) जयपुर (b) चंडीगढ़
(c) हैदराबाद (d) बेंगलुरु

Q10. राज्य के नाम में परिवर्तन को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दर्शाया जाता है?

(a) सातवीं अनुसूची (b) पहली अनुसूची
(c) तीसरी अनुसूची (d) आठवीं अनुसूची

Q6. Following the suspension of recognition of the Table Tennis Federation of India (TTFI), which organization was directed to constitute an ad hoc committee to oversee the sport in India?

(a) Sports Authority of India
(b) Board of Control for Cricket in India
(c) International Table Tennis Federation
(d) Indian Olympic Association

Q7. Which tenure did Ram Nath Kovind serve as the President of India?

(a) 12th President, 2007–2012
(b) 13th President, 2012–2017
(c) 14th President, 2017–2022
(d) 15th President, 2022–Present

Q8. Where is the headquarters of Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) located?

(a) Mumbai (b) Kochi
(c) Kolkata (d) Visakhapatnam

Q9. Where was the BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting held on 12 August 2026?

(a) Jaipur (b) Chandigarh
(c) Hyderabad (d) Bengaluru

Q10. In which Schedule of the Constitution of India is a change in the name of a state reflected?

(a) Seventh Schedule
(b) First Schedule
(c) Third Schedule
(d) Eighth Schedule

उत्तरमाला (Answer Key)

1 B	2 C	3 C	4 C	5 B	6 D	7 C	8 C	9 A	10 B